

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,

BENCH AT INDORE

W.P NO.4179/2021

*Mahesh s/o Badrilal & one another vs. State of M.P &
others*

01.03.2021: (INDORE):

Shri B.S.Gandhi, learned counsel for the petitioners.

Shri Aditya Garg, learned Panel Lawyer for the
respondent/State.

Shri M.K.Sankhala, learned counsel for the
respondent/caveator.

Heard.

Petitioner has filed the present petition being aggrieved
by the order dated 02.02.201 passed by the Additional
Commissioner, Ujjain whereby the appeal filed by the
respondent has been allowed and the order passed by the
Tahsildar, Badnagar dated 26.06.2019 as well as the order
passed by the SDO, Badnagar dated 31.03.2020 have been
set aside.

Facts of the case in short are as under:

2. The land bearing survey No.1252, area 2.73 hectares,
situated at village Kharsoudkhurd, Tahsil Badnagar, district
Ujjain was recorded in the name of Janibai wd/o Bherulal
along with co-owners Badrilal, Ramnarayan, Dungarsingh,
Leelabai, Ramubai & Rajubai. The petitioners on the basis of
the Will of Janibai dated 28.05.2004 filed an application
under section 109 & 110 of the M.P Land Revenue Code

before the Tahsildar for mutation of their names after the death of Janibai on 25.10.2018. In the said application Patwari Moja Gram Kharsoudkhurd was impleaded as non-applicant. The Tahsildar has directed for publication of notice and thereafter except the respondent the other co-owners filed an affidavit in support of the respondent that they have no objection if the name of the petitioners are recorded in place of Janibai. On the basis of the aforesaid, the Tahsildar has passed an order in favour of the petitioners on 26.06.2019.

3. The respondent came to know about the aforesaid order and filed a review petition before the Tahsildar on 24.08.2019 which has been dismissed by way of noting in the said application itself by the Tahsildar. Thereafter, he preferred a first appeal before the SDO which has been dismissed vide order dated 31.03.2020. Thereafter he preferred a second appeal before the Additional Commissioner which has been allowed. The operative part of the order passed by the Additional Commissioner is reproduced below:

“5.3 – ग्राम खरसौदखुर्द स्थित भूमि सर्व नम्बर 1252 रकबा 2.73 हैक्टर भेरूलाल पिता हीरालाल कुलमी के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी। भेरूलाल की मृत्यु के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 59 ग्राम सभा बैठक क्रमांक-6 दिनांक 04.04.2003 द्वारा जुंगरसिंह रामनारायण बद्रीलाल पिता भेरूलाल, लीलाबाई, रामुबाई, राधाबाई पिता भेरूलाल व जानीबाई बेवा भेरूलाल का नामान्तरण स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी के पक्ष में जानीबाई के द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत नहीं की गयी है बल्कि प्रश्नाधीन भूमि जानीबाई को उसके पति भेरूलाल के द्वारा

वार्डिलोपार्जित रूप से प्राप्त हुई थी और पैतृक भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है इस तथ्य को विचारण न्यायालय के द्वारा नजरंदाज किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो वसीयत प्रस्तुत की गयी है। उसमें 1/7 हिस्सा की वसीयत किये जाने के तथ्य के स्पष्ट न होने पर विचारण न्यायालय के द्वारा किस आधार पर उक्त भूमि के 1/7 भाग पर नामांतरण आदेशित किया गया है ? विचारण न्यायालय को वसीयत के आधार पर नामांतरण करने के पूर्व सहखातेदार व विधिक वारिसों को सूनवाई का अवसर दिा जाना चाहिये था, जो नहीं दिया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन नामांतरण आदेश को चुनौती दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31/03/2020 पारित किया है उसके संबंध में अपीलार्थी पक्ष के तथ्य से सहमत होने का तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि दिनांक 31/03/2020 को कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन होने से प्रकरणों में सुनवाई सीमित थी और अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है, अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय का आदेश सरसरी तौर पर स्थिर रखा है जबकि उनके द्वारा वारिसों को सुनवाई का अवसर न दिये जाने एवं पैतृक सम्पत्ति की वसीयत के तथ्य को नजरंदाज किया गया है। उक्त आधार पर विचारण एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश विधिक धरातल पर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं।

6- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय न्यायालय तहसीलदार, तहसील बडनगर जिला-उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-6/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2019 और अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड बडनगर जिला-उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 98/अपील/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2020 को विधिसम्मत पारित नहीं होने से अपास्त किया जाता है।”

I have heard learned counsel for the parties and perused the record.

4. Shri Gandhi, learned counsel for the petitioners submits that the petitioners have already filed a civil suit

claiming declaration of title on the basis of the Will of Janibai. It is settled law that revenue authorities are not competent to examine the Will and decide the title. The notice was not given to Doongarsingh in the proceeding under section 109 & 110 of the MPLR Code, the Additional Commissioner has not committed any error while allowing the appeal. It is settled law that any findings recorded by the revenue authorities are not binding on the civil court and all are subject to the final outcome civil Court. Since the parties are already before the civil Court, therefore, it would not be proper to comment on the merit of the case. Let the title be decided by the civil Court. The petition is dismissed.

(VIVEK RUSIA)
JUDGE

hk/